साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 13-19 जनवरी 2025 वर्ष-10, अंक-39

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

सीएम ने पशुपालन विभाग की समीक्षा ली बैठक, गाय पालन से सीएनजी बॉयोगैस संयंत्र की स्थापना को करेंगे प्रोत्सहित

बड़ी नगर पालिकाओं में भी बनाई जाएंगी अत्याधुनिक गौशालाएं

गौशालाओं में हर गाय 40 रुपए प्रतिदिन दे रही मध्यप्रदेश सरकार

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश सरकार गौ-संरक्षण एवं गौ-संवर्धन के लिए निरंतर कार्य कर रही है। हमारा प्रयास है गौ-वंश की उचित देखभाल हो, उन्हें समुचित आहार एवं पोषण मिले और इसके साथ पशुपालकों की आय भी बढ़े। इसके लिए सरकार कई योजनाएं ला रही है। प्रदेश में पशुपालन एवं दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। पंजीकृत गौशाला में रहने वाले पशुओं को पहले 20 रुपए प्रति दिन प्रति पशु आहार अनुदान दिया जाता था, जिसे अब बढ़ाकर 40 रुपए किया जा रहा है। दुग्ध उत्पादकों को बोनस दिए जाने की भी सरकार की योजना है। उन्होंने कहा कि गौ-वंश पालन से सीएनजी बॉयोगैस संयंत्र की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने मंत्रालय में पशुपालन एवं डेयरी विभाग की समीक्षा बैठक ली। बैठक में पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार लखन पटेल, मुख्य सचिव अनुराग जैन, अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव मनीष रस्तोगी, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी उमाकांत उमराव उपस्थित थे।

2190 गौ-शालाएं

सीएम ने कहा कि प्रदेश में 3.15 लाख गौ-वंश के लिए 2190 गौ-शालाएं संचालित की गई है। इनमें से प्रशासकीय स्वयं सेवी संस्थान द्वारा 627 गौ-शालाएं संचालित की जा रही है। इनमें 1.95 लाख गौ-वंश और मुख्यमंत्री गौ-सेवा योजना के अंतर्गत 1563 गौ-शालाओं में 1.20 लाख गौ-वंश रखे गए हैं।

टैग का बदलेगा रंग

पशुपालन एवं डेयरी मंत्री लखन पटेल ने सुझाव दिया कि पालतू एवं निराश्रित गौ-वंश की पहचान के लिए उन्हें अलग-अलग रंग के टैग लगाए जाएं, जिससे गौ-वंश की पहचान आसान हो सके। मंत्री ने बॉयो सीएनजी संयंत्र लगाने जाने की भी बात कही। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इन पर सहमति व्यक्त की।

गौ-शालाओं का निरीक्षण कराएं

मुख्यमंत्री ने बैठक में निर्देश दिए कि प्रदेश में संचालित सभी गौ-शालाओं का निरीक्षण करवाया जाए। अनुदान की राशि का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। गौ-शालाओं के संचालन में समाज का भी पूरा सहयोग लिया जाना चाहिए। गौ-शाला में गौ-वंश के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिएं। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि पंचायतवार अभियान चलाकर गोचर भूमि खाली कराई जाए। घरों में गौ-वंश पालने के लिए भी शीघ्र योजना बनाई जाए।

कुपोषित बच्चों को दें गाय का दूध

गाय का दूध अत्यंत पोषक होता है। बच्चों के कुपोषण को दूर करने में इसका अहम योगदान है। गाय के दूध के उत्पादन और विपणन पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। कुपोषित बच्चों को गाय का दूध उपलब्ध कराया जाए। प्रदेश के बड़े नगरों भोपाल, इंदौर, जबलपुर की तरह अन्य बड़ी नगर पालिकाओं में भी आधुनिक गौ-शालाओं का निर्माण किया जाएगा। प्रदेश में 187.00 लाख गौ-वंश है इनमें से 90.96 प्रतिशत यानी 170.537 लाख देसी नस्ल के गौ-वंश है।

बछिया उत्पादन पर फोकस

मुख्य सचिव अनुराग जैन ने सुझाव दिया कि गौ-वंश की नस्ल सुधारने एवं बछिया उत्पादन के लिए सेक्स सॉर्टेड सीमन का अधिकाधिक उपयोग किया जाए। प्रमुख सचिव उमराव ने बताया कि 20 वीं पशु संगणना के अनुसार प्रदेश में एक करोड़ 87 लाख गौ-वंश है।

2190 पंजीकृत गौ-शालाएं

प्रदेश में 2190 पंजीकृत गौ-शालाएं हैं, जिनमें 627 अशासकीय स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित और 1563 गौशालाएं मुख्यमंत्री गौ सेवा योजना अंतर्गत संचालित हैं। इन गौ-शालाओं में कुल 3 लाख 15 हजार गौ-वंश है, जिन्हें अनुदान दिया जाता है। इसके लिए वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 252 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान किया गया है। जनवरी-2025 से अनुदान राशि 40 रुपए किए जाने पर इस वित्त वर्ष में 34 करोड़ 65 लाख रुपए के अतिरिक्त प्रावधान की आवश्यकता होगी।

बड़ी उपलब्धिः 15 हजार क्विंटल कीमत, सागर में धरती के लाल का कमाल

एक एकड़ में उगा डाला 36 किस्म का गेहूं

सागर। जागत गांव हमार

सागर के एक किसान ने कमाल कर दिया है, उसने अपनी एक एकड़ जमीन पर 36 किस्मों के गेहूं को उगाया है। यह सभी विलुप्तप्राय देसी बीज हैं, जिनके संरक्षण के लिए और समाज के बीच इन गेहूं को लाने के लिए किसान ने अपने खेत में बोवनी की है। 36 प्रकार का गेहूं लगाने के लिए उसने अपने छोटू ट्रैक्टर से इसमें क्यारी बनाई और एक-एक क्यारी में एक-एक प्रकार का गेहूं बोया है, क्यारी के बीच में जो छोटी-छोटी सी मेढ़ है, उन पर धना को बोया गया है, ताकि गेहूं की कोई भी वैरायटी मिक्स ना होने पाए। इस सीजन 36 वैरायटी को उगाने के बाद इसे कुछ नई वैरायटी भी बनाई जाएगी, जिनका बीज सिलेक्शन विधि से चयन होगा। शहर से करीब 8 किमी दूर कपूरिया ग्राम में मल्टी लेयर फार्मिंग के जनक आकाश चौरसिया के की ओर से यह प्रयोग किया गया है। वह पिछले 10 साल से खेती में नए-नए तरह की इन्वेंशन करते आ रहे हैं। पिछले साल 1 एकड़ में उन्होंने 16 तरह के गेहूं को उगाया था, लेकिन इस बार 16 से बढ़कर 36 प्रकार के गेहूं की बोवनी की है। वह अपने फार्म हाउस पर हर महीने 7 दिन का फ्री प्रशिक्षण देश भर के किसानों को देते हैं। ऐसे में आकाश चौरसिया मानते हैं कि जो भारत के पुराने औषधि गुणों से भरपूर बीज हैं, उनको बढ़ावा देना चाहिए ताकि किसानों की आर्थिक आय बढ़े और बीमारियों पर अंकुश लगे।

हर वैरायटी गुणों से भरपूर

युवा किसान आकाश चौरसिया अपने इस प्रयोग को लेकर कहते हैं कि भारत के जो पुराने देसी बीज हैं वह किसी दवा से कम नहीं है, इन वैरायटी में कोई शुगर को कंट्रोल करता है तो कोई कब्ज खत्म कर देता है, कोई माइग्रेन दूर करता है तो कोई दिमाग को तंदुरुस्त रखता है। यानी इसमें जितनी भी वैरायटी हैं सब किसी न किसी गुण से भरपूर है।

15 हजार प्रति क्विंटल

इन गेहूं में 4000 से लेकर 15000 प्रति क्विंटल की बिक्री वाली वैरायटी शामिल हैं। वहीं उत्पादन की बात करें तो 12 क्विंटल प्रति एकड़ से लेकर 25 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उपज देती हैं। दो पानी की सिंचाई में और पांच पानी की सिंचाई वाली फसल शामिल है। 90 दिन से लेकर 140 दिन में पककर तैयार होने वाली किसमें लगाई गई हैं।

इस वैरायटी के गेहूं काली मूछ, सोना-मोती या पीतांबरा, खपली, कठिया, बंशी, बसंती, प्रताप, सर्जना, मालविका बसंती, सरवती, मोतीबासी, हंसराज, श्री, खैरा, नीलांबर, गुलांबरी, काला गेहूं, 306, 307, 315, 322, कुदरत, लाल गेहूं जैसी 36 देशी वैरायटी शामिल हैं।

गणतंत्र दिवस समारोहः शामिल होंगे सरपंच और अन्नदाता

10 हजार अतिथियों को भेजा गया निमंत्रण

भोपाल। भारत हर साल 26 जनवरी को अपना गणतंत्र दिवस मनाता है। इसी बीच देश अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस 76 वें गणतंत्र दिवस समारोह में जन भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य के तहत कर्तव्य पथ पर होने वाली गणतंत्र दिवस परेड में इस बार लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। आमंत्रित अतिथियों में सरपंच, आपदा राहत कार्यकर्ता, स्वयं सहायता समूह के सदस्य, कारीगर और अलग-अलग सरकारी योजनाओं के लाभार्थी जैसे विविध पृष्ठभूमि के लोग शामिल होंगे। वहीं, आमंत्रित सदस्यों में कृषि, पर्यावरण संरक्षण, स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों के साथ-साथ प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेने वालों पर भी विशेष ध्यान रखा गया है। आमंत्रित अतिथियों की सूची में सरपंच, शीर्ष प्रदर्शन करने वाले गांव के सरपंचों और कृषि से जुड़ी योजनाओं के लाभार्थियों को बुलाया गया है। इनमें शामिल हैं- पीएम कुसुम योजना के लाभार्थी, कृषि अवसंरचना निधि योजना, किसान उत्पादक संगठन, पद्म पुरस्कार विजेता किसान, पीएम किसान, पीएमएफबीवाई, जीवंत गांवों के अतिथि, कृषि ऋण समितियां, कृषि सखी, उद्योग सखी आदि, पीएम यशस्वी, हथकरघा कारीगर, हस्तशिल्प कारीगर, विभिन्न योजनाओं के विशेष उपलब्धि प्राप्त करने वाले और आदिवासी लाभार्थी, आशा, पीएम सूर्य घर योजना के लाभार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले ओम मत्स्य संपदा योजना के लाभार्थी, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाभार्थी हैं।

» ठंड में अधिक उत्पादन व कम मांग से सब्जियों के दाम गिरे

भाव नहीं मिलने से पशुओं को खिलाने को मजबूर किसान

मप्र में 2-3 रुपए किलो बिक रहे टमाटर-गोभी

» मप्र में टमाटर और गोभी के भाव गिरने से किसान परेशान

» लागत न निकलने पर फसल मवेशियों को खिलाई जा रही

बड़वानी। जागत गांव हमार

नए वर्ष में ठंड का असर बढ़ने से साग-सब्जियों के भावों में कमी आने लगी है। कुछ माह पूर्व तक अपने रंग अनुरूप सुर्ख भावों को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाला टमाटर अब बेभाव हो चुका है। हालत यह है कि स्थानीय सब्जी मंडी में भाव नहीं मिल रहे हैं। ऐसे में लागत व परिवहन का खर्च भी नहीं निकलने पर किसान अपनी फसल मवेशियों को खिलाने को मजबूर हो रहे हैं। क्षेत्र के किसान टमाटर के साथ ही फूल गोभी के भी भाव नहीं मिलने पर मवेशियों को खिला रहे हैं। सेगांव के किसान राधेश्याम गेहलोत ने बताया कि खेत में टमाटर लगाए थे। उत्पादन भी अच्छा निकल रहा है, लेकिन मंडियों में भाव नहीं मिलने से लागत निकालना तो दूर, मंडी तक उपज ले जाने का परिवहन महंगा पड़ने लगा है। ऐसे में खेत से निकली फसल को मवेशियों को खिलाने को मजबूर हो रहे हैं।

किसानों के पास कोई विकल्प नहीं

किसानों के अनुसार जब टमाटर के भाव बढ़ते है तो देश-प्रदेश में खासा हल्ला मचाया जाता है, लेकिन जब भाव औंधे मुंह गिरते है तो किसानों का पक्ष नहीं लेता। किसानों की मानें तो इस फसल के लिए शासन से न तो कोई अनुदान मिलता है और न ही सब्जियों की तरह टमाटर पर एमएसपी लागू है। ऐसे में सीजन में कई बार टमाटर सहित अन्य सब्जियां बेभाव बिकने से किसानों के सामने अपनी उपज को फेंकने की बजाय मवेशियों को खिलाने के अलावा कोई विकल्प नहीं रहता।

उत्पादन पर अनुदान नहीं

किसानों के अनुसार अभी टमाटर के भाव बेभाव हो गए है। शासन टमाटर पर कोई अनुदान नहीं देती, लेकिन टमाटर का केचअप बनाकर बेचने वाले उद्योग पर 50 फीसदी तक अनुदान देती है। किसान के एक किलो टमाटर की आज 10 रुपए कीमत नहीं है, लेकिन बाजार में 100 ग्राम केचअप इससे अधिक राशि में बिकता है। हालांकि शासन किसानों को कैचअप उद्योग के लिए प्रोत्साहित कर रही है, लेकिन क्षेत्र में उद्योग-कारखाने नहीं होने से किसानों को इसका वाजिब लाभ नहीं मिल पाता।

दो एकड़ की गोभी पशुओं को खिलाई

इसी तरह दो दिन पूर्व राजपुर क्षेत्र के ऊंची गांव के किसान रामलाल ने मंडियों में भाव नहीं मिलने पर दो एकड़ में लगाई गोभी फसल मवेशियों के हवाले कर दी। गोभी तुड़ाई का खर्च न हो, इसके लिए खेत में ही मवेशियों को छोड़कर फसल खिला दी। किसान के अनुसार मंडी में गोभी के दाम भी चार से पांच रुपए किलो मिल रहे हैं, जो घाटे का सौदा साबित हो रहा है।

खरीददार नहीं मिल रहे

किसान मंसाराम पंचोले के अनुसार जिल के कई गांवों में किसान टमाटर की खेती करते है। वर्तमान में इसका भाव औंधे मुंह गिरने से मंडियों में खरीदार नहीं मिल रहे है। वहीं जो भाव दिए जा रहे हैं, वो किसानों की फसल की लागत अनुरूप नहीं है। हालत यह हो गई है कि मात्र 2 से 3 रुपए किलो में टमाटर खरीदी की जा रही है, जबकि उत्पादन लागत ही इससे तीन गुना लगती है। उधर सब्जी विक्रेताओं के अनुसार ठंड के दिनों में सब्जियों के दामों में कमी आती है। बाजार में खेरची में टमाटर 8 से 9 रुपए किलो मिल रहा है। खेरची में 15 से 20 रुपए किलो तक बिक रहा है। भावों में कमी का सीधा कारण अधिक उत्पादन होना और मांग कम होना है।

अभी नए गेहूं को मंडियों में आने में करीब दो महीने की देरी

मप्र में सरकारी गेहूं में आई 100 रुपए क्विंटल की तेजी

उज्जैन। जागत गांव हमार

भारतीय खाद्य निगम का गेहूं ऑनलाइन नीलामी में ऊंचे में 3105 रुपए क्विंटल बिक गया। बीते सप्ताह मंडी नीलामी में 75 रुपए क्विंटल की तेजी आ गई है। बता दें कि अभी सरकार ने दो लाख टन गेहूं नेपाल को निर्यात करने का निर्णय लिया है। इस कारण भी गेहूं में जारी तेजी का असर हुआ है। यह साल गेहूं की तेजी में रिकॉर्ड बनाने को अग्रसर है। बाजार में गेहूं की काफी कमी देखी जा रही है। मंडियों में आवक सिमटकर हजार से बारह सौ बोरी की रह गई है। तेजी का असर मिल क्वालिटी पर काफी पड़ा है।सरकारी गेहूं की साप्ताहिक ऑनलाइन नीलामी में आटा मिल वालों ने उच्चतम भाव 3105 रुपया क्विंटल दिए, जो सागर डिपो का बताया जा रहा है। निम्नतम भाव 3000 रुपये क्विंटल रहे। 35 हजार क्विंटल की बिक्री की गई। बीते तीन दिनों में मंडी नीलामी में करीब 75 रुपए क्विंटल की तेजी आ गई, कारण 1300 बोरी की आवक रही। चमक वाला लोकवन गेहूं 3270 रुपया क्विंटल बिक गया। पोषक के भाव 3144 रुपए क्विंटल रहे।

» सरकार ने दो लाख टन गेहूं नेपाल को निर्यात करने का निर्णय लिया

» अभी मंडियों में आवक सिमट कर हजार से बारह सौ बोरी की रह गई

अभी नया गेहूं को मंडियों में नहीं आएगा

इससे स्पष्ट है कि उपभोक्ताओं को मिल रहा महंगा आटा, गेहूं से सरकार को फर्क नहीं पड़ रहा है। मालूम हो, अभी नए गेहूं को मंडियों में आने में करीब दो माह की देरी है। जब तक बाजार में गेहूं की किल्लत बनी रहने की संभावना है।

बाजार पर नहीं पड़ा असर

गज्जर गेहूं 3100 से 3150 रुपया क्विंटल चल रहा है। मिल क्वालिटी गेहूं के भाव 3170 रुपए क्विंटल तक बिक गया है। ब्रोकर संजय खंडेलवाल के अनुसार गेहूं की तेजी के दौरान दिल्ली व गुजरात में गेहूं के भाव में 50 रुपए क्विंटल की मंदी भी आई। इसका असर बाजार पर नहीं पड़ा।

बाजार में किल्लत जारी

विश्लेषकों का मानना है कि सरकार को अब खाद्यान्न की महंगाई से कोई सरोकार नहीं रहा। सरकारी गोदामों में ही गेहूं की कमी है। बाजार में किल्लत जारी है। बावजूद खुली बिक्री के तहत गेहूं बिक्री का आवंटन बढ़ाने की बजाय नेपाल की जरूरत की पूर्ति की जा रही है।

-केंद्रीय योजनाओं का लाभ दिल्ली सरकार के अंतर्गत किसानों को नहीं मिल रहा

-देश की राजधानी दिल्ली में सोलर पंप योजना व फसल बीमा योजना लागू नहीं

किसानों ने शिवराज को गंभीर समस्याएं बताईं, तो वे द्रवित हो उठे और कहा

किसानों के हितों के लिए झोंकूंगा ताकत मैं दिलाकर रहूंगा उनका अधिकार

भोपाल। जागत गांव हमार

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों से संवाद के अपने नियमित कार्यक्रम के अंतर्गत दिल्ली में सफदरजंग रोड स्थित अपने निवास स्थान पर दिल्ली राज्य के किसान संगठनों, किसान प्रतिनिधियों और बड़ी संख्या में आए किसान भाइयों-बहनों से चर्चा की। इस दौरान चौहान ने कहा कि मेरा सौभाग्य है कि दिल्ली के किसानों से मिलने और चर्चा करने का अवसर मिला। किसानों ने कृषि मंत्री को अनेक गंभीर समस्याएं बताईं, तो वे द्रवित हो उठे और कहा कि राजधानी दिल्ली में किसान परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं। मैं दिल्ली के किसानों के हितों के लिए पूरी ताकत लगाऊंगा, किसानों का अधिकार दिलाकर रहूंगा। किसानों द्वारा बताए जाने पर शिवराज सिंह ने इस बात पर दु:ख जताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की किसानों के लिए लागू अनेकानेक योजनाओं का लाभ दिल्ली राज्य सरकार के अंतर्गत किसानों को नहीं मिल पा रहा है।

शिवराज से बड़ी संख्या में दिल्ली के किसान मिलने पहुंचे तो उन्होंने राज्य सरकार से जुड़ी बहुत-सी परेशानियां बयां की। इस पर शिवराज ने कहा कि उन्हें पहले भी दिल्ली के किसानों ने समस्याएं बताई थीं, जिस पर उन्होंने तुरंत ही दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी को पत्र लिखा था। मेरा केवल उनसे हाथ जोड़कर इतना कहना है, मेरा स्वभाव नहीं है किसी को गाली देना, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप पत्र का जवाब दे दो, जवाब भी मत दो, बहन आतीशी, लेकिन भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाओं को आप दिल्ली के किसानों के लिए लागू कर दीजिए।

ये योजनाएं दिल्ली में लागू नहीं

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार ने बागवानी विकास मिशन लागू कर रखा है, जिसमें किसानों को बीज-खाद, कृषि यंत्रों, पालीहाउस, ग्रीनहउस आदि पर सब्सिडी मिलती है, जो केंद्र सरकार देती है। राज्य सरकार के माध्यम से, लेकिन यह मिशन दिल्ली की राज्य सरकार ने लागू नहीं किया है। इसी तरह, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना में सिंचई के लिए 50 प्रतिशत सब्सिडी केंद्र सरकार देती है, लेकिन इसके सहित कृषि संबंधी केंद्र सरकार की अन्य कई योजनाएं आतरशी की सरकार ने लागू ही नहीं की है। यहां कृषि है, किसान है लेकिन उन्हें किसाना का दर्जा ही नहीं मिला हुआ है, दिल्ली में कृषि मंत्री ही नहीं है। दिल्ली में एमएसपी पर खरीद ही नहीं होती है, जो हम राज्य सरकार के माध्यम से ही करते हैं। किसानों की फसल खराब हो जाती है लेकिन दिल्ली में राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ही लागू नहीं की है। इस तरह से कृषि एवं किसान कल्याण की योजनाओं के लाभ से दिल्ली के किसान वंचित हैं, यह दु:ख की बात है।

केजरीवाल सबसे बड़ी आपदा

चौहान ने दु:खी मन से कहा-मैं एक बात बड़ी तकलीफ के साथ कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की अनेकानेक योजनाओं का लाभ दिल्ली के किसानों को नहीं मिल रहा है। दिल्ली के किसानों के लिए प्राकृतिक आपदा से बड़ी आपदा है केजरीवाल।

दिल्ली सरकार से मांगा जवाब

शिवराज सिंह ने कहा कि मुझे गाली दो या दाउद कहो, उससे मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन भारत सरकार की किसान कल्याण की योजनाएं तो दिल्ली के किसानों के लिए लागू करो, किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो। चौहान ने कहा कि केंद्र द्वारा राज्यों के माध्यम से ही योजनाएं लागू की जाती है, यह व्यवस्था की बात है। दिल्ली में किसान हित में व्यवस्था परिवर्तन होना चाहिए। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने दिल्ली की मुख्यमंत्री से अपील की कि बहन आतिशी, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में किसानों का अहित न करो।

दिल्ली में ट्रैक्टर भी कमर्शियल

शिवराज ने कहा कि दिल्ली में ट्रैक्टर भी कमर्शियल माना जाता है। रजिस्ट्रेशन का ज्यादा पैसा लगता है, यहां गंदे पानी में फसल बर्बाद होती है। यहां सोलर पंप योजना लागू नहीं है, फसल बीमा योजना लागू नहीं है। इस कारण दिल्ली राज्य के किसान बहुत परेशान हैं। शिवराज ने दिल्ली राज्य सरकार से कहा कि आप प्रस्ताव भेजो, पैसा ले जाओ और किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाओ, लेकिन, अब इसमें आतीशी कहीं मुझे दाऊद कहती हो, कहीं गाली देती हो तो इसका कोई औचित्य नहीं है, मैं तो फिर प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो।

किसानों ने सुनाई व्यथा

शिवराज सिंह प्रत्येक मंगलवार को किसान संगठनों से मुलाकात करते हैं। चौहान अब तक 15 से अधिक किसान संगठनों से भेंट कर चुके हैं। राज्यों के दौरों पर भी किसान संगठनों से मुलाकात कर रहे हैं। जब दिल्ली के किसान कृषि मंत्री से मिलने पहुंचे तो उन्हें बताया कि आज से 10-15 साल पहले दिल्ली का किसान खुद को हिंदुस्तान का राजा समझता था, लेकिन अब दिल्ली का किसान पूरे देश में सबसे पिछड़ा हो गया है। पिछले 40-50 साल के अंदर दिल्ली में तीन मास्टर प्लान लागू हो चुके हैं, परंतु हमारे यहां पर कोई कंसोलिडेशन नहीं हुआ। एक तरफ दिल्ली सरकार कहती है कि दिल्ली अब वर्ल्ड क्लास की होगी, दिल्ली तो वर्ल्ड क्लास होगी लेकिन मेरा गांव सड़ जाएगा। किसानों ने कहा कि हमारे गांव में रास्ते नहीं हैं, रास्तों में पूरा पानी भरा हुआ है। पूरे दिन खेत में काम करने के बाद सब्जियों को स्टेशन तक लाने में कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। किसानों को खेतों में ठीक रास्ता मिल जाए तो वह अपनी साईकिल या ट्रैक्टर से सब्जियां ले जा सकता है। हमारे ट्रैक्टर्स को कमर्शियल वाली अवधि में ना लाया जाए, पूरे जीवन में किसान एक ही बार ट्रैक्टर खरीद पाता है। गत 10 दिनों में एमसीडी ने ट्रैक्टर छीनकर खड़े करवा दिए हैं, वो 18 रुपए किलो के हिसाब से पैसा लेते हैं। दिल्ली में सरासर तानाशाही हो रही है।

दुविधा दूसरे राज्यों के किसानों से अलग

किसानों ने बताया कि दिल्ली के किसान की दुविधा दूसरे राज्यों के किसानों से अलग है। दिल्ली में मृदा स्वास्थ्य योजना लागू नहीं है। दिल्ली के किसान केंद्र सरकार से मिलने वाली सभी सब्सिडियों से वंचित हैं। यहां किसानों को फसल बीमा योजना का लाभ नहीं मिलता है। अधिकारी कहते हैं, दिल्ली में किसी प्रकार की फसल बीमा योजना नहीं है। ड्रिप एरीगेशन पर पड़ोसी राज्य में 50 से 80 प्रतिशत तक की सब्सिडी है, लेकिन दिल्ली के किसान को सिंचाई योजना में ड्रिप इरीगेशन पर सब्सिडी नहीं मिलती है। पड़ोसी राज्यों में सोलर योजना है लेकिन दिल्ली में सोलर योजना भी नहीं है। दिल्ली राज्य सरकार की रुचि कृषि विज्ञान केंद्रों में भी नहीं है, जबकि दूसरे राज्यों में कई कृषि विज्ञान केंद्र होते हैं। दिल्ली का किसान प्राकृतिक खेती से वंचित है, कई प्राकृतिक खेती करता हूं लेकिन उस पर भी उन्हें सब्सिडी नहीं मिलती है. लालडोरे की भी समस्या है।

केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का आह्वान, ऑयल पाम मिशन में तेजी लाएं सभी राज्य

इधर, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी राज्य सरकारों से अपील की कि वे ऑयल पाम मिशन के तहत अपने प्रयासों को तेज करें ताकि देश में तिलहन मिशन को बढ़ावा मिल सके। ऑयल पाम मिशन का पूरा नाम नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स-ऑयल पाम है। इस मिशन के जरिये केंद्र सरकार देश में तिलहन के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है ताकि खाद्य तेलों के आयात को कम किया जा सके। घरेलू तेल पाम की खेती को बढ़ावा देने के लिए शुरू किए गए इस मिशन का लक्ष्य 2025-26 तक 6.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को तेल पाम के बागानों के अंतर्गत लाना है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और अन्य तेल पाम उगाने वाले राज्यों की कृषि-जलवायु क्षमता का लाभ उठाने पर विशेष जोर दिया जा रहा है। कुछ क्षेत्रों में इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है, जबकि अन्य को अपने प्रयासों में तेजी लाने की जरूरत है। बांटे गए फंड का कम उपयोग और पाम वृक्षारोपण लक्ष्यों को प्राप्त करने में देरी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि राज्यों को बाधाओं को दूर करके और उपलब्ध संसाधनों को जुटाकर अपने वृक्षारोपण लक्ष्यों को हासिल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। एनएमईओ-ओपी के तहत

पर्याप्त फंड के साथ, राज्यों को बुनियादी ढांचे के विकास, किसान समर्थन और वृक्षारोपण विस्तार के लिए संसाधन उपयोग को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि मंत्री ने कहा कि राज्यों को किसानों की भागीदारी को भी बढ़ाना चाहिए, गलत सूचना जैसी चुनौतियों से निपटना चाहिए और किसानों की संतुष्टि और निरंतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए सहायता के वितरण में तेजी लानी चाहिए। पारदर्शिता और दक्षता में सुधार के लिए सरकार ने जियो-मैपिंग और ड्रोन निगरानी के माध्यम से डिजिटल निगरानी जैसी पहल शुरू की है। मंत्री ने राज्यों से इन उपायों में पूर्ण सहयोग करने का आग्रह किया। इसके अलावा, किसानों को बाजार की अस्थिरता से बचाने के लिए व्यवहार्यता मूल्य (वीपी) तंत्र शुरू किया गया है। किसानों को यह लाभ पहुंचाने के लिए राज्यों को समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर समय पर हस्ताक्षर सुनिश्चित करने चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने खाद्य तेल उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए एकजुट प्रयास के महत्व को दोहराया। उन्होंने कहा कि मिशन के लक्ष्यों को साकार करने में केंद्र और राज्य सरकारों, कार्यान्वयन एजेंसियों और किसानों के बीच एक मजबूत साझेदारी महत्वपूर्ण होगी।

क्या किसानों को अपने पेयजल स्रोतों की जाँच करने की आवश्यकता है?

» डा. दीपक कुमार
» डा. शुभी खरे
- मृदा एवं जल संरक्षण इंजीनियरिंग विभाग, गोविंद बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखंड

भारत दुनिया का सातवां सबसे बड़ा देश है और जनसंख्या के मामले में विश्व स्तर पर दूसरे स्थान पर है। बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर विषय है क्योंकि बढ़ती जनसंख्या के कारण पेयजल की उपलब्धता पर पहले से भी अधिक जोर देने की आवश्यकता है। भारत में जल की उपलब्धता हमेशा से ही एक चर्चित विषय रहा है जिसके लिए संविधान द्वारा विभिन्न नियम और कानून बनाए गए हैं। इससे संबंधित एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा उपलब्ध भूजल की गुणवत्ता है। विशेषकर भारत में पीने के पानी के लिए भूजल सबसे महत्वपूर्ण संसाधनों में से एक है।

विभिन्न स्त्रोतों से भूजल में प्रदूषण के कारण, कुछ शहरों और गांवों में, भूजल पीने के लिए सुरक्षित नहीं रह गया है। ऐसी कई बीमारियां हैं, जिनमें से कुछ जानलेवा भी हो सकती हैं, जो प्रदूषित भूजल पीने से हो सकती हैं, जैसे हैजा, डायरिया, हेपेटाइटिस आदि। इनमें से डायरिया विश्व स्तर पर, विशेष कर भारत में, सबसे अधिक फैलने वाली बीमारी है। डब्लूएचओ के अध्ययन के अनुसार डायरिया के कारण वैश्विक स्तर पर लगभग 12 लाख लोगों की मृत्यु हुई, जिसमें से 49प्रतिशत हिस्सेदारी केवल भारत की है। डायरिया से अधिकतर मौतें 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों में देखी गई हैं। साथ ही असुरक्षित पानी पीने के कारण 36.4प्रतिशत मृत्यु दर का है। इस असुरक्षित जल का एक कारण प्रदूषण है जो विभिन्न गतिविधियों जैसे लैंडफिल्स, पेट्रोलियम अवशिष्टों, औद्योगिक अपशिष्टों, रासायनिक अपशिष्टों, अनियंत्रित खतरनाक अपशिष्टों, सेप्टिक प्रणाली, प्राकृतिक गतिविधियों आदि से आता है। इन गतिविधियों के कारण विभिन्न हानिकारक कार्बनिक या अकार्बनिक प्रदूषण पानी में मिल जाते हैं और इसे मानव उपभोग के लिए असुरक्षित बना देते हैं। अनेकों कार्बनिक संदूषक पीने के पानी में पाए जा सकते हैं जिनके कारण विभिन्न बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं। निम्नलिखित एक तालिका है जिसमें अकार्बनिक संदूषकों और उनके कारण होने वाली समस्याओं की सूची है।

तालिका संख्या 1: कार्बनिक संदूषक से होने वाले रोग

क्र	कार्बनिक संदूषक	समस्याएं
1	कीटनाशक	विषाक्तता, सिरदर्द, चक्कर आदि
2	दवाइयों	कैंसर और लीवर की क्षति सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं
3	प्लास्टिसाइज़र	कैंसर और तंत्रिका एवं प्रजनन प्रणाली को क्षति
4	वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों	विषाक्तता, सिरदर्द और अन्य कई स्वास्थ्य समस्याएं
5	क्लोरीनयुक्त विलायक	विषाक्तता, सिरदर्द सहित कई स्वास्थ्य समस्याएं
6	डाइअक्सिन	विषाक्तता, सिरदर्द सहित कई स्वास्थ्य समस्याए

अकार्बनिक संदूषक कार्बनिक संदूषकों की तुलना में अधिक घातक होते हैं क्योंकि उन्हें पानी से पुन: प्राप्त नहीं किया जा सकता है। कुछ अकाबर्जनिक संदूषक और उनके कारण होने वाली बीमारियों का वर्णन नीचे दी गई तालिका में किया गया है। उपर्युक्त अधिकांश बीमारियाँ शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत को अधिक प्रभावित करती हैं क्योंकि उनमें दूषित पेयजल और मानव स्वास्थ्य पर इसके खतरनाक प्रभावों के बारे में जानकारी का अभाव है। दूषित जल के सेवन से होने वाले घातक परिणामों का एक उदाहरण उत्तर प्रदेश का सोनभद्र जिला है। वर्ष 2012 में किए गए एक अध्ययन के अनुसार सोनभद्र के गांवों में पीने के पानी में फ्लोराइड और पारा का स्तर अनुमेय सीमा से लगभग 2.1 गुना अधिक था। 'भारत की ऊर्जा राजधानी' के नाम से मशहूर सोनभद्र में कई थर्मल पावर प्लांट हैं। सोनभद्र जिले में, क्षेत्र में बहुत अधिक खनन गतिविधियाँ होती हैं, जो भूजल और सतही जल निकायों को गंभीर रूप से प्रदूषित करती हैं। इन बढ़ते स्तरों के परिणामस्वरूप 2021 में सोनभद्र के गांवों में बीमारी की लहर फैल गई, जिसके कारण लगभग 40 ग्रामीणों की जान चली गई, जिनमें बच्चे भी शामिल थे। पीने के पानी में फ्लोराइड, पारा और अन्य प्रदूषकों के उच्च स्तर का मुख्य कारण खनन और क्षेत्र में बड़ी संख्या में उद्योग हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के 2022 के एक अध्ययन के अनुसार, मध्य प्रदेश में हर साल लगभग 37.7 मिलियन लोग दूषित पेयजल के कारण होने वाली बीमारियों से पीड़ित होते हैं और लगभग 1.5 मिलियन बच्चे हर साल डायरिया से मर जाते हैं। इसी तरह उत्तर प्रदेश में कानपुर नगर और कानपुर देहात भी दूषित पेयजल के कारण मानव स्वास्थ्य में चुनौतियों का सामना कर रहे हैं। 2024 में, एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की अध्यक्षता वाली पीठ ने औद्योगिक टेनरियों से उपचार के बिना छोड़े जाने वाले अपशिष्टों के मामले की सुनवाई की, जिसके कारण प्रभावित क्षेत्रों में एक सर्वेक्षण किया गया। सर्वेक्षण के नतीजों से पता चला कि अत्यधिक प्रदूषित पानी के सेवन के कारण, कानपुर नगर और कानपुर देहात के विभिन्न क्षेत्रों में सर्वेक्षण के दौरान 1460 लोगों की जांच में से लगभग 600 लोगों को त्वचा रोग, 49 लोगों को फेफड़ों के रोग और 146 लोगों को यकृत रोग पाए गए। गड्ढों में भरे पानी और घरेलू आपूर्ति में क्रोमियम की मात्रा अधिक होने के कारण कानपुर नगर और कानपुर देहात के विभिन्न हिस्सों में त्वचा रोग, फेफड़ों की बीमारी और मानसिक स्वास्थ्य समस्या के साथ-साथ अस्थमा का खतरा बढ़ रहा है।

तालिका संख्या 2: अकार्बनिक संदूषक और उनसे होने वाले रोग

क्रं	अकार्बनिक संदूषक	समस्याएं
1	हरताल	कैंसर, त्वचा पर घाव, हृदय रोग, मधुमेह और संज्ञानात्मक विकास
2	क्रोमियम	जिगर और गुर्दे की क्षति, आंतरिक रक्तस्राव, श्वसन क्षति, जिल्द की सूजन और अल्सर
3	ताँबा	पेट और आंतों की परेशानी, लीवर और किडनी की क्षति, और एनीमिया
4	सीसा, पारा और अन्य भारी धातुएँ	तंत्रिका संबंधी विकार और कैंसर
5	नाइट्रेट और फॉस्फेट	
6	सल्फेट	निर्जलीकरण और जठरांत्र संबंधी रोग
7	फ्लोराइड	स्केलेटल फ्लोरोसिस, डेंटल फ्लोरोसिस, दांतों का मलिनकिरण, और/या दांतों में गड्ढा पड़ना

कॉम्बाइन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम को कानूनी रूप से अनिवार्य करना चाहिए

जलाने से नहीं, दबाने से होगा पराली का समुचित इंतजाम

1970 के दशक से भारतीय खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली हरित क्रांति का श्रेय मुख्य रूप से बौनी उच्च उत्पादक क्षमता वाली गेहूं की किस्मों और धान की किस्मों की शुरुआत को दिया जाता है। भारतीय शोधकर्ताओं ने इन फसलों में और सुधार किया और साथ ही रासायनिक उर्वरकों के उपयोग और भूजल आधारित नलकूप सिंचाई को बढ़ावा दिया। खासतौर पर पंजाब, हरियाणा जैसे उत्तर-पश्चिमी राज्यों में इस पर खास ध्यान दिया गया।

इसका परिणाम यह हुआ कि 1961 से 2021 के बीच इन राज्यों में धान की खेती के क्षेत्रफल में 10 गुना वृद्धि हुई। वर्तमान में पंजाब और हरियाणा में कुल धान का क्षेत्रफल 50 लाख हेक्टेयर से अधिक हो गया है, जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 2.5 करोड़ मीट्रिक टन से अधिक है। इसमें सुगंधित बासमती चावल और लगभग 3 करोड़ मीट्रिक टन धान के भूसे का उत्पादन शामिल है।

फसल चक्र और धान के भूसे का जलना: धान की कटाई अक्टूबर-नवंबर में की जाती है। इसके बाद किसानों के पास अगली फसल—जैसे गेहूं, सरसों, आलू और सब्जियों—की बुवाई के लिए केवल 15-20 दिन का समय होता है। इस कम समय में खेत तैयार करने के लिए किसान धान के भूसे को जलाने का विकल्प अपनाते हैं, जिससे उत्तर-पश्चिम भारत, विशेषकर दिल्ली-एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण फैलता है। इस स्थिति को हिमालय क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाओं और धीमी हवा की गति (4 किमी प्रति घंटा से कम) जैसे मौसमी कारकों ने और अधिक जटिल बना दिया है।

इस पर्यावरणीय समस्या का समाधान करने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकारों ने पिछले 6 वर्षों में 6,000 करोड़ रुपए खर्च कर भारी मशीनरी वितरित की। लेकिन, इन 30 मिलियन मीट्रिक टन धान के भूसे के प्रबंधन के लिए सिर्फ 15 दिन का समय होने के कारण, ये प्रयास अप्रभावी साबित हुए। इसका परिणाम यह निकला कि वायु गुणवत्ता सूचकांक में कोई उल्लेखनीय सुधार नहीं हुआ।

धान की कटाई के लिए अधिकांश किसान कॉम्बाइन हार्वेस्टर का उपयोग करते हैं, जिनका डिजाइन मुख्यत: गेहूं की कटाई के लिए किया गया है। ये मशीनें खेत में असामान्य रूप से लंबे भूसे छोड़ती हैं। इन भूसे को हटाने के लिए श्रम और संसाधनों की आवश्यकता होती है, जो किसानों के लिए व्यावहारिक और किफायती नहीं हैं। इस स्थिति ने किसानों को पयाज़्वरणीय रूप से हानिकारक पराली जलाने के तरीकों को अपनाने पर मजबूर किया।

हरियाणा सरकार को 2018 से कॉम्बाइन हार्वेस्टर के इस दोषपूर्ण डिजाइन की जानकारी थी और उन्होंने मशीनों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम को अनिवार्य बनाने का आदेश दिया था। लेकिन प्रशासनिक स्तर पर इस फैसले को ठीक से लागू नहीं किया गया, जो पराली जलाने की समस्या का मुख्य कारण बन गया।

स्थानीय प्रबंधन: समाधान का बेहतर तरीका: इंसिटू (स्थानीय) फसल अवशेष प्रबंधन विधियां पयाज़्वरण-अनुकूल हैं। इन विधियों के तहत भूसे को मिट्टी की गहराई (6 इंच से नीचे) में मिलाया जाता है, जिससे मिट्टी के पोषक तत्व सुरक्षित रहते हैं। इसके बाद अगली फसल की बुवाई के साथ प्रति हेक्टेयर 50 किलोग्राम यूरिया के उपयोग से भूसा एक महीने में जैविक पदार्थ में बदल जाता है, जिससे अगली फसल पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ता।

हालांकि, इंसिटू प्रबंधन केवल तभी संभव होगा जब कॉम्बाइन हार्वेस्टर में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाया जाए, जो भूसे को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट सके। सरकार को कानूनी रूप से अनिवार्य करना चाहिए कि सभी कॉम्बाइन हार्वेस्टर मालिक अपनी मशीनों में स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगवाएं। इससे छोटे किसान पारंपरिक कृषि उपकरणों जैसे हारो का उपयोग करके आसानी से भूसे को मिट्टी में मिला सकेंगे। इससे समय पर अगली फसल की बुवाई संभव होगी, पराली जलाने की समस्या खत्म होगी, और वायु प्रदूषण नियंत्रित होगा। इसके साथ ही मिट्टी की उपजाऊ क्षमता, जल धारण क्षमता, और वायु संचार बेहतर होगा। यह समाधान सभी संबंधित पक्षों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा।

जलवायु परिवर्तन से ठंडे खून वाले जीवों में बढ़ रहे हैं घातक संक्रमण

दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन के कारण तापमान में भारी वृद्धि हो रही है और इससे संक्रामक रोगों का प्रकोप बढ़ सकता है, जिससे प्रजातियों का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। तापमान में वृद्धि और संक्रमण मिलकर जीवों के स्वास्थ्य को किस हद तक नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह स्पष्ट नहीं है।

ब्रिटिश कोलंबिया विश्वविद्यालय (यूबीसी) के एक नए अध्ययन से पता चलता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण कोरल, कीड़े और मछली जैसे ठंडे खून वाले जीवों के लिए जीवाणु और फंगल संक्रमण घातक हो सकते हैं। जिससे पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है, इसकी वजह से लोगों पर बढ़ते तापमान का और क्या-क्या असर पड़ सकता है इस बारे में कई सवाल उठते हैं।

गर्म होती दुनिया में ठंडे खून वाले जीवों पर असर: शोधकर्ताओं ने बैक्टीरिया, फंगल और अन्य संक्रमणों से पीड़ित ठंडे खून वाले जानवरों पर 60 प्रयोगात्मक अध्ययन किए, जिसमें पाया गया कि ठंडे खून वाले जानवर सीधे तापमान पर निर्भर होते हैं और इसलिए, ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो सकते हैं। अध्ययनों में जमीनी कीटों, मछलियों, मोलस्क और कोरल सहित 50 प्रजातियों को शामिल किया गया जो ग्रह पर सबसे अधिक जैव विविधता वाले और सबसे अधिक खतरे वाले पारिस्थितिकी तंत्रों में से कुछ हैं।

शोधकर्ताओं ने सांख्यिकीय मॉडलों का उपयोग करते हुए पाया कि जीवाणु संक्रमण से ग्रस्त ठंडे खून वाले जीवों के सामान्य पयाज़्वरणीय परिस्थितियों की तुलना में अधिक तापमान के संपर्क में आने पर उनके मरने की अधिक आशंका होती है।

फंगल संक्रमण और ठंडे खून वाले जीव: शोध में विश्लेषण से पता चला कि फंगल रोगजनकों से संक्रमित जीवों ने एक विशिष्ट तापमान सीमा के भीतर गर्मी के प्रभाव को महसूस किया। तापमान बढ़ने पर वे अधिक बार नहीं मरे, जब तक कि तापमान कवक की आदर्श सीमा की ओर नहीं बढ़ा, जिसे थर्मल ऑप्टिमम के रूप में जाना जाता है। इस बिंदु पर, संक्रमित जानवरों के मरने की अधिक आशंका जताई गई थी। हालांकि जब तापमान इतना ज्यादा हो गया कि कवक जीवित नहीं रह सके, तो संक्रमित जानवरों में मृत्यु दर कम हो गई।

इन निष्कर्षों से पता चलता है कि बढ़ती गर्मी से ठंडे खून वाले जानवरों के लिए अधिक खतरा हो सकता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

मुख्यमंत्री डॉ.मोहन यादव ने कहा-कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार प्रदान किए जाएंगे

मप्र में देश की डेयरी कैपिटल बनने की क्षमता

» विक्रम विवि उज्जैन में डेयरी टेक्नोलॉजी कोर्स पाठ्यक्रम शामिल होने पर संगोष्ठी आयोजित

» पशुपालन का डिग्री कोर्स अब जबलपुर के साथ उज्जैन में भी छात्रों को प्रदाय किया जाएगा

» दुग्ध उत्पादन में नौ प्रतिशत की भागीदारी के साथ मध्यप्रदेश का देश में तीसरे पायदान पर

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि वर्तमान परिदृश्य में भारत सबसे युवा देशों में से एक है। प्रधानंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन अनुरूप हमें युवा शक्ति का संपूर्ण उपयोग राष्ट्रहित और विकास में करना है। डेयरी टेक्नोलॉजी युवाओं के लिए एक नए मार्ग खोलता है। भगवान श्रीकृष्ण की शिक्षा स्थली उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में डेयरी टेक्नोलॉजी की अकादमिक डिग्री कोर्स की शुरुआत की जा रही है। पशुपालन का डिग्री कोर्स अब जबलपुर के साथ उज्जैन में भी छात्रों को प्रदाय किया जाएगा। भविष्य में अन्य विश्वविद्यालयों में भी यह कोर्स राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अनुसार प्रदान किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने विक्रम

विवि उज्जैन के स्वर्ण जयंती सभागृह में पशुपालन विभाग एवं विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित संगोष्ठी को सबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि डेयरी टेक्नोलॉजी में प्रशिक्षित कौशल प्राप्त युवा डेयरी टेक्नोलॉजी का उपयोग कर अपने मजबूत इरादों और मेहनत से दूध उत्पादन में मध्यप्रदेश को सर्वोच्च स्थान पर ले जाएंगे। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है और दुग्ध उत्पादन में 9 प्रतिशत की भागीदारी के साथ मध्यप्रदेश का देश में तीसरा स्थान है। प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का औसत 673 ग्राम है, जबकि राष्ट्रीय औसत 471 ग्राम का है। हमें इन उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना है। प्रदेश की भौगोलिक स्थिति, अथाह जल संपदा और उर्वरा भूमि को देखते हुए सही दिशा में समेकित प्रयास करने पर हम डेयरी के क्षेत्र में देश का नंबर-1 राज्य बनाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश को देश का डेयरी कैपिटल बनाने के लिए दूध की प्रति लीटर क्रय के आधार पर सरकार पशुपालकों को बोनस भी प्रदान करेगी।

सिंचाई का रकवा भी बढ़ाएंगे

इसी के साथ पशुधन के लिए पर्याप्त भोजन उपलब्ध कराने के लिए भी सरकार संपूर्ण रूप से प्रयासरत है। इसके लिए सिंचाई का नया रकवा बढ़ाया जाएगा। मालवा का क्षेत्र कृषि में भी समृद्ध है और अब पशुपालन में भी समृद्ध बनेगा। स्वागत भाषण संभागायुक्त एवं उज्जैन दुग्ध संघ प्रशासक संजय गुप्ता द्वारा दिया गया। उन्होंने मुख्यमंत्री को पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी लिंक परियोजना और केन-बेतवा नदी लिंक परियोजनाओं से कृषि एवं पशुपालन को फायदा पहुंचाने पर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम का कुलसचिव ने आभार माना। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती वंदना के साथ की गई। कार्यक्रम स्थल पर मुख्यमंत्री को एनसीसी कैडेट्स द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। मुख्यमंत्री का स्वागत वेद ऋचाओं की गूंज के बीच शाल, श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर विश्वविद्यालय के कुलगुरु अर्पण भारद्वाज द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव द्वारा विक्रम विवि के एक्टिविटी कैलेंडर का विमोचन किया। कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद बालयोगी उमेशनाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा, डीके पांडेय, राजेश कुशवाह और विवि का स्टाफ एवं बड़ी संख्या में छात्र उपस्थित रहे।

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विवि, ग्वालियर

कुलगुरु ने किया औचक निरीक्षण

शिवपुरी। जागत गांव हमार

राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के कुलगुरू प्रोफेसर अरविन्द कुमार शुक्ला द्वारा गत दिवस कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी का अचानक निरीक्षण कर भ्रमण किया।

प्रो. शुक्ला ने केन्द्र पर उपस्थित स्टॉफ की जानकारी लेते हुए कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी पर चल रही गतिविधियों एवं प्रदर्शन इकाइयों में प्रमुख मशरूम उत्पादन, शेडनेट हाउस में प्याज पौध उत्पादन, पॉलीसहनेट हाउस में अधिक मूल्यवान फलों की खेती जिसमें स्ट्रॉबेरी परीक्षण सह प्रदर्शन, लाल भाजी का छोटे स्तर पर बीजोत्पादन, प्राकृतिक खेती इकाई सह प्याज प्रदर्शन की तैयारी, मत्स्य पालन एवं रंगीन मछलियों एवं अजोला उत्पादन, फसल संग्रहालय, अंजीर वृक्षों से फलों का उत्पादन एवं उनके फलों का प्रसंस्करण के विषय पर भी मार्गदर्शन दिया। भ्रमण के दौरान कृषि विज्ञान केन्द्र पर नवीन स्थापित की जा रही ड्रैगनफ्रूट यूनिट के 44

पौधों जिसमें लाल एवं सफेद गूदे वाली ड्रैगनफ्रूट की प्रजाति शामिल है का भी निरीक्षण कर तकनीकी जानकारियों से अवगत कराया। जिन्हें ड्रैगनफ्रूट की उत्पादन इकाई में किया जा सके।

कुलगुरू को कृषि विज्ञान केन्द्र के विकास के लिए कार्यों पर जानकारी देते हुए आगामी लक्ष्यों के बारे में भी विस्तार से बतलाया गया जिससे केन्द्र के विकास को और अधिक गति मिल सके। वही कुलगुरू प्रो. शुक्ला द्वारा भी कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी के कार्यों एवं की जा रही गतिविधियों पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए आवश्यक मार्गदर्शन भी दिया गया। इस अवसर पर केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. पुनीत कुमार, वरिष्ठ वैज्ञानिक (सस्य विज्ञान) डॉ. एमके भार्गव, वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों में जेसी गुप्ता, डॉ. पुष्पेन्द्र सिंह, डॉ. एएल बसेड़िया, योगेश चन्द्र रिखाड़ी, डॉ. नीरज कुमार कुशवाहा, स्टेनो आरती बंसल, एवं इंद्रजीत गढ़वाल उपस्थित रहे।

नेचुरल और ऑर्गेनिक खेती पर रहेगा मोदी सरकार का फोकस

जलवायु अनुकूल खेती के लिए केंद्र बढ़ाएगा बजट

भोपाल। केंद्र सरकार आगामी 1 फरवरी को 2025-26 के लिए बजट पेश करने जा रही है। इस बजट में कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए जारी होने वाली रकम बढ़ाई जा सकती है, क्योंकि, केंद्र का फोकस जलवायु अनुकूल खेती के साथ ही नेचुरल और ऑर्गेनिक फार्मिंग पर अधिक है। इसके अलावा दलहन और तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता भी प्राथमिकता में है, जबकि, केमिकल फर्टिलाइजर से बचने के लिए सरकार इसके विकल्पों को लाने पर जोर दे रही है। केंद्र सरकार की ओर से आम बजट पेश किए जाने में लगभग 20 दिन बचे हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले बजट में जलवायु अनुकूल बीज किस्मों की उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से कई प्रोत्साहनों की घोषणा की जा सकती है। खास तौर पर अनाज, दालों और तिलहनों के साथ ही रासायनिक उर्वरक के इस्तेमाल में कमी लाने के लिए प्राकृतिक खेती जैसी कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने का लक्ष्य भी रखा गया है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट में कहा गया है कि बजट 2025-26 में कई फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए रोडमैप भी दिए जाने की उम्मीद है। इसमें बेमौसम बारिश, तापमान में वृद्धि और बारिश पैटर्न में क्षेत्रीय बदलाव जैसी चरम मौसम की घटनाओं को ध्यान में रखा जाएगा। यह देखते हुए कि जलवायु परिवर्तन ने कृषि को प्रभावित करना शुरू कर दिया है। अगस्त 2024 में प्रधानमंत्री मोदी ने 61 फसलों की 109 अधिक उपज देने वाली जलवायु-अनुकूल और बॉयो फोर्टिफाइड किस्में जारी की थीं।

वैज्ञानिक सलाहकार समिति की बैठक सम्पन्न

पराली की समस्या से निपटने हैप्पी और सुपर सीडर को दें बढ़ावा

बैतूल। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, बैतूल की रबी पूर्व वैज्ञानिक सलाहकार समिति बैठक सम्पन्न हुई। कार्यक्रम के आरंभ में केन्द्र प्रमुख डॉ. व्हीके वर्मा ने मुख्य अतिथि डॉ. डीपी शर्मा, संचालक विस्तार सेवायें, जनेकृविवि जबलपुर का स्वागत किया। केन्द्र के वैज्ञानिक आरडी बारपेटे ने सभी सम्मानित सदस्यों का स्वागत किया। उक्त बैठक की अध्यक्षता करते हुए डॉ. डीपी शर्मा ने बैतूल जिले की स्थानीय विलुप्त फसल जैसे कडु जीरा, जंगली भिंडी एवं तिखाड़ी आदि को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र के वैज्ञानिकों को निर्देशित किया। साथ ही खेती में पराली की समस्या को दूर करने के लिए हैप्पी सीडर एवं सुपर सीडर के प्रयोग को बढ़ावा देने का सुझाव दिया। केन्द्र

की शस्य वैज्ञानिक डॉ. मेघा दुबे ने केन्द्र का प्रगति प्रतिवेदन एवं आगामी कार्य योजना का विस्तृत ब्यौरा माननीय सदस्यों के समक्ष प्रस्तुत किया।

उक्त बैठक में राष्ट्रीय पादप आनुवंषिक अनुसंधान ब्यूरो, क्षेत्रीय केन्द्र, अकोला महाराष्ट्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. सुनील श्रीराम गोमासे, बैतूल जिले के कृषि संबंधित विभागों के विभाग प्रमुख/प्रतिनिधि, प्रगतिषील कृषक, आदान विक्रेता के अध्यक्ष सहित 34 सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार व्यक्त वैज्ञानिक डॉ. संजीव वर्मा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में डॉ. संजय जैन, डॉ. एमपी इंगले, नेपाल बारस्कर, सौरभ मकवाना, रेखा तिवारी आदि की सक्रिय भागीदारी रही।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा-नायब तहसीलदार केवल नायब नहीं, बल्कि नायाब बनें

-नई संभावनाओं के लिए प्रतिबद्धता के साथ अधिकारी, शासकीय सेवा में करें प्रवेश

दुग्ध उत्पादन को 20 फीसदी और कृषि रकबे को एक करोड़ हेक्टेयर तक ले जाना टारगेट

भोपाल। जागत गांव हमार

भोपाल के रवींद्र भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में सीएम डॉ. मोहन यादव ने शासकीय सेवा में नियुक्ति पाने वाले 362 अफसरों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस अवसर पर सीएम ने एक अहम घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में बैकलॉग के पदों को भरने जा रही है। मध्यप्रदेश में एमपीपीएससी के पिछले तीन वर्ष के पद 2025 में भरे जाएंगे। परीक्षाएं अलग-अलग होंगी। वहीं सीएम ने नए अधिकारियों को संदेश दिया कि अधिकारी का मतलब अधिक कार्य करने वाला होना चाहिए। हम सभी को यह ध्यान रखना होगा कि हमारे मन में अहंकार न हो। एक अधिकारी का काम सेवा भाव से जनता के हित में काम करना है।

सीएम ने कहा कि अब वह समय गया जब कृषि की पढ़ाई के लिए केवल कृषि कॉलेज अनिवार्य था। अब प्रदेश के सभी कॉलेजों में बीएससी एग्रीकल्चर कोर्स पढ़ाया जाएगा। विटनरी के मामले में भी राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विश्वविद्यालयों को मेडिकल कॉलेज खोलने की अनुमति दी गई है। सीएम ने गौपालन को प्रोत्साहित करने की योजनाओं पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हम किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं। देश में दुग्ध उत्पादन में मध्यप्रदेश तीसरे स्थान पर है। हमारा लक्ष्य दुग्ध उत्पादन की क्षमता को 9 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत तक पहुंचाना है। इससे देश के किसानों और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। प्रदेश में गौ-माता की बेहतर देखभाल के लिए गौ-शालाओं का विस्तार किया जा रहा है। इसी क्रम में भोपाल सहित सभी बड़े शहरों में 10-10 हजार क्षमता की गौ-शालाएं संचालित करने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध है।

-काम करें, अहंकार नहीं,जनता के विश्वास को बनाए रखें
-सभी जिलों में सायबर तहसील को लागू करने वाला देश का पहला राज्य मध्यप्रदेश
-मुख्यमंत्री ने 3 विभागों के 362 अधिकारियों-कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र किए प्रदान
-राजस्व मंत्री करन सिंह वर्मा बोले-पटवारियों के चक्कर होंगे खत्म

दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता

किसानों की आय बढ़ाने में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका दुग्ध उत्पादन की है। किसानों की आय बढ़ाने के प्रयासों में दुग्ध उत्पादन को प्रोत्साहित करना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। इससे किसानों को सीधे तत्काल लाभ प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि दस गाय से अधिक गौ-पालन करने वालों को अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा। गांवों में सड़क, घर-घर नल से जल जैसी सुविधाएं मिलने से गौपालन भी सुविधाजनक हुआ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नव चयनित अधिकारी से यही अपेक्षा है कि वे अपनी प्रतिभा और क्षमता को निरंतर बेहतर करें। विकास की नई संभावनाओं के लिए प्रतिबद्धता के साथ अधिकारी सेवा में प्रवेश करें। प्रदेश में कृषि के रकबे को अगले 5 साल में 48 लाख हेक्टेयर से एक करोड़ हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य है। इस उद्देश्य से हमें सभी प्रबंध बेहतर करने होंगे। राजस्व अधिकारियों की नियुक्तियां, कृषि और पशुपालन विभाग के अमले में विस्तार इसमें सहायक होगा। राज्य सरकार द्वारा कृषि और पशु चिकित्सा की शिक्षा सुविधा का भी विस्तार किया जाएगा, इसमें नई शिक्षा नीति भी सहायक है।

नायाब बनने की उम्मीद

सीएम ने नए अधिकारियों को कहा कि नायब तहसीलदार केवल नायब नहीं, बल्कि नायाब बनें। प्रदेश की सेवा में अपना सर्वश्रेष्ठ योगदान दें और जनता के विश्वास को बनाए रखें। आज नियुक्ति पाने वाले अधिकारी अपने काम से सेवा की नई इबारत लिखें।

-राजस्व मंत्री ने कहा- ईमानदारी से काम करें

राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने कहा- एमपी देश का ऐसा राज्य है, जहां नामांतरण, बंटवारा और सीमांकन का काम तेजी से हो रहा है। उन्होंने साइबर तहसील की पहल का जिक्र करते हुए बताया कि इससे किसानों को पटवारियों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। फौती नामांतरण के मामले में अगर 30 दिन से ज्यादा समय लगता है तो संबंधित पटवारी पर कार्रवाई होगी। जो लोग नई नियुक्ति पा रहे हैं, वे यह सुनिश्चित करें कि वे ईमानदारी से काम करें।

मंत्री ने की घोषणाएं-अब कृषि विस्तार अधिकारी

मप्र के कृषि विकास मंत्री एदल सिंह कंषाना ने घोषणा की कि अब ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी को कृषि विस्तार अधिकारी के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने मोहन यादव की सराहना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा किसानों और युवाओं की खुशहाली के लिए काम करते हैं।

मंत्री लखन का संदेश-पद की गरिमा बनाए रखें

मंत्री लखन पटेल ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने पद की गरिमा बनाए रखें। आप जिस पद पर जा रहे हैं, वहां लोगों की सेवा करना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। आपकी सेवा और कार्यशैली से लोग आपको याद रखें, यही असली सफलता है।

मुख्यमंत्री ने भारतीय वन सेवा के अधिकारियों को दी बधाई, कहा

वन क्षेत्र और वन्य जीवों की गतिविधियों में इजाफ मध्यप्रदेश की सबसे बड़ी उपलब्धि

भोपाल। जागत गांव हमार

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के पन्ना जैसे क्षेत्र जहां वन्य जीवों की स्थिति शून्य हो गई थी, वहां भी वन अधिकारियों के प्रयासों के परिणामस्वरूप वन्य जीवों की गतिविधियां पुन: आरंभ हुईं, यह अपनी सेवा के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है और वे बधाई के पात्र हैं। वर्तमान में प्रदेश के पास हीरा है, चीता है और अब तो गजराज भी मध्यप्रदेश का रूख कर रहे हैं। प्रदेश का वन क्षेत्र समृद्ध है। वर्ष 2003 से 2021 के मध्य वन क्षेत्र में 1063 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। भोपाल देश की एकमात्र ऐसी राजधानी है, जिसके आस-पास आसानी से टाइगर देखे जा सकते हैं। यह हमारे प्रदेश के लिए सुखद और पर्यावरण की दृष्टि से बड़ी उपलब्धि है। मुख्यमंत्री पंडित खुशीलाल आयुर्वेद महाविद्यालय सभागार में दो दिवसीय आईएफएस (भारतीय वन सेवा) मीट और वानिकी सम्मेलन के शुभारंभ सत्र को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने दीप प्रज्वलन के साथ कर तथा मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर सम्मेलन का शुभारंभ किया। सम्मेलन में वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार, अपर मुख्य सचिव वन अशोक वर्णवाल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख असीम श्रीवास्तव तथा अन्य आईएफएस अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री को रूद्राक्ष का पौधा भेंटकर उनका स्वागत किया गया।

मप्र में प्रचुर वन संपदा विद्यमान

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस प्रकार के मीट परस्पर संवाद, मित्रता के भाव, अनुभव साझा करने और बेहतर कार्य संस्कृति विकसित करने के लिए आवश्यक है। मप्र में प्रचुर वन संपदा विद्यमान है। पुरातत्व, भू-गर्भ शास्त्र, पर्यावरण, वनस्पति शास्त्र सहित कई विधाओं में अध्ययन व शोध की अपार संभावना विद्यमान हैं। वन विभाग को इन क्षेत्रों में अध्ययन को प्रोत्साहन और सहयोग प्रदान करने के लिए पहल करना होगी। पर्यटन क्षेत्र को प्रोत्साहित करने के लिए भी गतिविधियों का विस्तार किया जाए। उन्होंने रातापानी के संदर्भ में ग्रामों के विस्थापन की चुनौती का प्रभावी तरीके से सामना करने के लिए वन अमले की प्रशंसा की। राज्य शासन द्वारा वनों के विकास और नवाचारी गतिविधियों के संचालन के लिए हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा।

वन और वन्य जीव हमारी पहचान

वहीं समारोह के दौरान प्रदेश के वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री दिलीप अहिरवार ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध मप्र के वन और वन्य जीव हमारी पहचान है। शासन इनके संरक्षण और सवंर्धन के लिए कटिबद्ध है। प्रदेश में जनभागीदारी को केन्द्र में रखकर अनेक गतिविधियां और कार्यक्रम चलाए जा रहे है। राज्य शासन द्वारा वनों के संरक्षण और संवर्द्धन के लिए की गई ईमानदार एवं प्रभावी पहल का परिणाम है कि प्रदेश के वन आवरण में स्थायित्व आने के साथ ही वन्य प्राणियों के प्रबंधन की दिशा में किए गए प्रयासों को सराहा गया है।

पशुपालन मंत्री ने किया पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भोपाल का निरीक्षण, कहा

गायों के आहार में हरा चारा और साइलेज को शामिल करें

भोपाल। जागत गांव हमार

पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) लखन पटेल ने कहा है कि गौवंश के आहार में हरा चारा और साइलेज को शामिल करें। इससे गौवंश का स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि होती है। मंत्री ने भदभदा, भोपाल स्थित जर्सी पशु प्रजनन प्रक्षेत्र भोपाल का निरीक्षण किया। मंत्री ने निरीक्षण के दौरान प्रक्षेत्र पर उपलब्ध गौवंश के आहार की संरचना के विषय पर चर्चा की। उन्होंने गौवंश के आहार में साइलेज को शामिल करने के निर्देश दिए और कहा कि इससे दुग्ध उत्पादन में हुई बढ़ोतरी का अध्ययन किया जाए। साथ ही हरा चारा और साइलेज को आहार में सम्मिलित करने से दुग्ध उत्पादन में आने वाले वित्तीय भार का आंकलन भी किया जाए। मंत्री द्वारा निर्देश दिए गए कि अच्छी नस्ल के प्रजनन योग्य सांड सालरिया गो अभयारण्य, आगर मालवा और अन्य गौशालाओं को भेजे जाएं। उन्होंने प्रक्षेत्र के गोबर गैस प्लांट को पुन चालू करने के निर्देश भी दिए। हरा चारा उत्पादन एवं दुग्ध उत्पादन आदि के संबंध में जानकारी भी ली। भ्रमण के दौरान संयुक्त संचालक पशुपालन डॉ. जीके वर्मा एवं संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।

किसान बोला-भविष्य में भूमि नहीं होगी, तो तकनीक ही लगानी पड़ेगी

एक खेत में सब्जी-बागवानी, फल-औषधीय क्रॉप, जमीन के हर हिस्से का किया इस्तेमाल

संयुक्त राष्ट्र विश्व जनसंख्या डैश बोर्ड 2023 के अनुसार भारत की जनसंख्या 142.86 करोड़ हो गई है। साल 2040 तक यह 163 करोड़ हो सकती है। ऐसे में भविष्य में खेती के लिए जमीन कम बचेगी। इसकी चिंता की है, नीमच के चौथी पास किसान भगत राम भाटी ने। वह कहते हैं कि आने वाले समय में जमीन नहीं होगी, तो टेक्नीक तो लगानी पड़ेगी।

नीमच। जागत गांव हमार

नीमच जिले के आमलीखेड़ा गांव के भगतराम अपने 5 बीघा खेत में सब्जी से लेकर फल, बागवानी, इलायची, बादाम और औषधीय फसलें उगा रहे हैं। खास बात है कि उन्होंने जमीन का छोटा सा टुकड़ा भी खाली नहीं छोड़ा। हर हिस्से में कुछ ना कुछ फसल उगाई है। रोजाना तीन से चार हजार रुपए भी कमा रहे हैं। इसके लिए खुद दिनभर खेत में पसीना बहाते हैं। नतीजा, गर्मी के दो महीने छोड़ साल भर एक के बाद एक उत्पादन लेते हैं। आसपास के लोग भी उनके यहां सीखने आते हैं।

तकनीक का प्रयोग कर पैसा कमाया जा सकता है- भगतराम भाटी का कहना है कि जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में खेती के लिए जमीन कम पड़ती जा रही है। रोजगार की समस्या भी हो रही है। इससे आने वाली पीढ़ी कैसे पेट भरेगी...कम जमीन में किस तरह अधिक मुनाफा लिया जा सकता है, इसके लिए तकनीक तो लगानी पड़ेगी, तभी गुजारा हो पाएगा। आजकल युवा खेती से दूर हो रहे हैं। तकनीक का प्रयोग कर और दिमाग लगाकर खेती से पैसा कमाया जा सकता है। शुरुआत में यूट्यूब पर खेती से संबंधित वीडियो देखे, इसी के साथ नया करने के बारे में सोचा। वैसे तो, शुरुआत से खेती कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयोग करीब चार साल पहले शुरू किया। जैसे, मैंने यह बगीचा लगाया, अब इसमें कलम करके नर्सरी तैयार हो गई है। एक बीघा में नर्सरी बन जाती है, इससे हजारों पेड़ तैयार हो जाएंगे। आमदनी भी शुरू हो जाएगी। खेत में पहले मिर्च लगाई, फिर सफेद मूसली लगाई। हालांकि मिर्च थोड़ी खराब हो गई थी। इसके बाद धनिया लगाया, जिससे उत्पादन हो रहा है। करेले के बीज भी लगाए हैं, धनिया खत्म होते-होते वह उत्पादन देने लग जाएगी। इसी तरह, पहले मक्का लगाया, उसके खत्म होने से पहले ही मटर लगा दी थी। मटर उत्पादन दे रही है। भिंडी भी लगा दी है, इसके खत्म होते-होते उत्पादन देने लगेगी।

खेत की मेड़ पर भी लगाए पपीते के पौधे

भगतराम ने खेत के चारों तरफ मेड़ पर करीब 250 पपीते के पेड़ उस जगह लगाए हैं, जहां ट्रैक्टर से जुताई नहीं हो सकती। यह हिस्सा अछूता रहता है। पिछले तीन साल से इससे फल भी ले रहे हैं। यही नहीं, पपीते के पौधों के बीच में खेत की तार फेंसिंग कर चारों तरफ गराडू, गिलकी, शकरकंद लगा दी है। भगत राम बताते हैं कि गर्मी के दो-तीन महीने में उपज नहीं लेते। इस दौरान जरूरी जुताई के साथ देसी खाद व अन्य उर्वरकता बढ़ाने वाले उत्पाद डालते रहते हैं, ताकि उपजाऊ क्षमता बनी रहे। भगतराम का कहना है कि वैसे तो फसलों के लिए पर्याप्त पानी है, लेकिन फिर भी स्प्रिंकलर के जरिए सिंचाई करते हैं। इससे जरूरत अनुसार पानी उपलब्ध होता है। पानी की बरबादी भी नहीं होती।

अब सीखने आते हैं युवा छात्र

भगतराम रोजाना करीब तीन से चार हजार रुपए की फसल मंडी में बेचने ले जाते हैं। वहां से लौटकर खेत के काम में जुट जाते हैं। साथ में सिर्फ उनकी पत्नी मदद करती है। तीनों बेटों को बंटवारा कर दिया है, ताकि आत्मनिर्भर हो सकें। वे समय-समय पर पिता का मार्गदर्शन लेते रहते हैं। अपने लिए पांच बीघा खेती रखी है। भगतराम बताते हैं कि करीब 10-15 साल पहले 8 लाख रुपए से ज्यादा का कर्ज था, लेकिन मेहनत से वह भी चुका दिया। भगतराम बमुश्किल चौथी क्लास तक पढ़े हैं। खास बात ये भी है कि न तो कहीं प्रशिक्षण लिया और न किसी का मार्गदर्शन। इसके बावजूद उनके पास स्मार्ट खेती के गुर सीखने एग्रीकल्चर के छात्र भी आते हैं। पड़ोसी और गांव के युवा किसान भी देखने आते हैं।

भगतराम ने अपने खेत को चार हिस्सों में बांटा

भगतराम बताते हैं कि पांच बीघा खेत को चार हिस्सों में बांटा है। इसमें दो बीघा में अमरूद, अंगूर, चीकू, संतरा, आम, पपीता, नींबू लगाए हैं। अब बादाम, इलायची, अंगूर, एपल बेर, अंजीर के पड़े भी लगाए हैं। इसमें अंजीर और एपल बेर में फल आ गए हैं। दूसरे हिस्से में बारिश में मक्का लगाया। मक्का कटने के साथ नीचे की ओर मटर लगाई। इसका उत्पादन वर्तमान में ले रहे हैं। इसके साथ भिंडी भी लगा दी है। मटर खत्म होने से पहले भिंडी उत्पादन देने लगेगी। इसी तरह, तीसरे हिस्से में बारिश के समय मिर्च बोई थी। उत्पादन शुरू होने से साथ पाल पर बीच में सफेद मूसली और धनिया पत्ती लगा दी। वर्तमान में तीनों उपज उत्पादन दे रही हैं। अब क्यारी में पानी देने की जगह पर करेले के बीज लगाए हैं। आने वाले दिनों उत्पादन मिलने लगेगा। भगतराम का अनुमान है कि करीब दो लाख रुपए की सफेद मूसली निकल आएगी। अब तक एक लाख रुपए की धनिया-मिर्च बेच चुका हूं। भगतराम का कहना है कि खेत के आखिरी हिस्से में डॉलर चने भी बो रखे हैं। चने की फसल जब डेढ़ महीने की हुई, तब इसके बीच में इसबगोल बो दी। चने की फसल कट जाएगी, तब तक इसबगोल तैयार हो जाएगी, जिससे एक ही समय में दो फसल का उत्पादन मिलेगा। खेत के एक हिस्से में बागवानी कर रखी है, जिसमें कई प्रजाति के फलदार वृक्ष लगाए हैं। आम की करीब 20 से 25 किस्में हैं, जिनमें छोटे-बड़े 200 पेड़ हैं। इसी तरह, संतरे के करीब 50 पेड़ हैं। अमरूद के भी करीब 25 पौधे हैं।

असफल होने के बाद भी नहीं हारी हिम्मत

जंगली झरबेरी के पेड़ पर उगा दिया एप्पल बेर, लखपति बना किसान

सागर। जागत गांव हमार

सागर जिले की मालथौन तहसील के ग्राम रजवांस में एक युवा किसान द्वारा झरबेरी के पौधों में ग्राफ्टिंग कर एप्पल बेर के नए पौधे तैयार किए गए हैं। कृषि तथा उद्यानिकी क्षेत्र में नवाचार करने वाले किसान ने छोटे से गांव में नया मॉडल पेश किया है। यह परंपरागत खेती से हटकर है और खरपतवार समझे जाने वाले झरबेरियों के झाड़ अब एप्पल बेरों से लदे हैं, जो किसान को मुनाफे का सौदा बन रहे हैं। बुंदेलखंड अंचल में किसानों के खेतों की मेड पर झरबेरी या देशी बेर के झाड़ बहुतायत उग जाते हैं, जिन्हें किसान प्रतिवर्ष काट-छांट देते हैं। इन झाड़ों से

बेर के फल तो पैदा होते हैं। लेकिन यह छोटे और गुणवत्ता विहीन रहते हैं। अमूनन किसान झरबेरी के इन झाड़ों को खरपतवार मानते हैं। लेकिन इस युवा किसान द्वारा खेतों के किनारे उगने वाली झरबेरी में बडिंग कर एप्पल बेर का पौधा बना दिया, जिनसे अब बंपर उत्पादन हो रहा है।

एप्पल बेर का वजन 100 से 120 ग्राम तक आ रहा है। किसान अंकित जैन ने बताया कि उन्होंने चार साल पहले भी ऐसा प्रयोग किया था। लेकिन वो असफल हो गए थे। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और अब खेतों के किनारे मेड पर उगने वाली झाड़ी जिसे झरबेरी कहते हैं, उनमें ग्राफ्टिंग कर एप्पल बेर की नई फसल तैयार कर ली है। जो कि छह महीने में पककर तैयार हो जाती है और उससे फल मिलने शुरू हो जाते हैं, जो कि बहुत ही लाभ का धंधा है।

वहीं, इस युवा किसान द्वारा किए इस नवाचार की सराहना कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यह बड़ी सरल प्रक्रिया है और अगर ऐसा जिले के सभी किसान करने लगे तो सागर एप्पल बेर निर्यात का केंद्र बन सकता है। वहीं, इस युवा किसान द्वारा किए गए कार्यों से अन्य किसान भी प्रभावित है तथा वह भी ऐसा नवाचार करना चाहते हैं।

पांच लाख पौधों को किया जा रहा तैयार

मध्यप्रदेश में किया जाएगा औषधीय पौधों का रोपण

भोपाल। जागत गांव हमार

प्रदेश में इस बार होने वाले पौधरोपण में उन पौधों को प्राथमिकता के आधार पर रोपने की योजना बनाई गई है, जो औषधीय पौधों की श्रेणी में आते हैं। इससे जहां पर्यावरण सुधार में फायदा होगा तो वहीं आयुर्वेद की दवाओं के उपयोग के लिए कच्ची सामग्री भी आसानी से मिल सकेगी। इसकी वजह से सरकार को भी राजस्व मिलने का रास्ता साफ हो जएगा। इन औषधीय पौधों की पौध तैयार करने का काम राजधानी की नर्सरियों में किया जा रहा है। अहमदपुर रोपणी में ऐसे पांच लाख पौधों को तैयार किए जाने पर काम किया जा रहा है। फिलहाल अब तक तीन लाख पौधे की नर्सरी तैयार की जा चुकी है, जबकि दो लाख पौधों की नर्सरी तैयार किए जाने का काम जारी है। इस रोपणी में शल्यकर्णी, श्योनाक हर्रा, बीजा, अर्जुन, रोहण जर जैसे 60 तरह के औषधीय पौधे उगाने का काम किया जा रहा है।

अलग-अलग जिलों में पौधे भेजे जाएंगे

इसके अलावा तीन्सा, हलदू, काला शीशम, धनकट, खरहर, धावड़ा, करधई, पापड़ा, और मैदा प्रजाति के पौधे भी उगाए जार हे हैं। इन सभी का उपयोग वृक्षारोंपण में किया जाना है। दरअसल, इस तरह के औषधीय पेड़ सतपुड़ा और विंध्य रेंज के जंगलों में पाए जाते हैं, लेकिन अब वे दुर्लभ श्रेणी में आ चुके हैं। इनके अलग-अलग हिस्सों का उपयोग विभिन्न प्रकार की बीमारियों के उपचार में किया जाता है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि अहमदपुर रोपणी में तैयार पौधों को भोपाल, सीहोर और रायसेन जिलों में रोपा जाएगा। इसी तरह प्रदेश भर की रोपणियों से पौधे लेकर अलग-अलग जिलों में पौधरोपण के लिए भेजे जाएंगे।

480 हेक्टेयर क्षेत्र में रोपे गए पौधे

पौधरोपण अभियान के तहत बीते साल भोपाल जिले में कुल 480 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधे लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम और हरित महोत्सव अभियान को भोपाल में एक वृक्ष भोपाल के नाम से भी प्रचारित किया गया था, जिसके अंतर्गत बड़ी संख्या में पौधरोपण किया गया। भोपाल नगर के साथ ही संपूर्ण भोपाल जिले में भी पौधे लगाए गए हैं। भोपाल के कलियासोत डेम, आदमपुर खंती, कीरत नगर, मुंगालियाकोट, समरधा जंगल रेंज और कलारा बैरसिया क्षेत्र में पौधरोपण किया गया था। इसमें से आदमपुर खंती में सबसे ज्यादा 15 हजार और इसके बाद भेल में 5000 पौधे रोपे गए थे। इसके अलावा अन्य जगहों पर करीब 400-400 पौधे रोपे गए हैं। इनमें नीम, बरगद, करंज, बांस और बेल के पौधे शामिल थे। इसके अलावा आम, जाम, चिरौंजी, सीताफल, महुआ, जामुन और आंवला जैसे फलदार पौधे समेत स्थानीय पौधे भी लगाए गए थे।

सागौन के भी 50 हजार पौधे लगाए जाएंगे

भोपाल वन मंडल में इस वर्ष 50 हजार सागौन के पेड़ लगाए जाने की योजना तैयार की गई है। यह प्रयास पर्यावरण संरक्षण और हरित क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। सागौन के वृक्ष भूमि की स्थिरता को बनाए रखते हैं और जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करते हैं। इसके अलावा यह प्रजाति इमारती लकड़ी में भी बेहद अहम स्थान रखती है।

किस प्रजाति में कौन से औषधीय गुण

शल्यकर्णी का पेड़ प्रदेश के विंध्य और मेकाल की पहाडियों में पाया जाने वाला एक अति दुर्लभ प्रजाति का वृक्ष है। 2008 में पारंपरिक इलाज करने वाले आदिवासी वैद्यों की वजह से इस पेड़ की पहचान हो सकी है। इसके पत्ते का लेप घावों को भरने में बेहद मददगार साबित होता है। इसी तरह से सोनापाठा को आयुर्वेद के ग्रंथों में श्यौनाक कहा गया है। गर्म तथा नम क्षेत्रों में पाया जाने वाला यह पेड़ अब दुर्लभ है। आयुर्वेदिक औषधियों दशमूलारिष्ट, अमृतारिष्ट, धन्वतरिघृत का यह मूल तत्व है। इसकी जड़, छाल, फूल, फल, बीज, लकड़ी और पत्तियां तक ज्वर, दमा, एलर्जी, खांसी, अतिसार, बदहजमी, प्रसूतिजन्य दुर्बलता आदि के इलाज में काम आती है। बीजा नामक वृक्ष को आयुर्वेद के ग्रंथों में विजयसार के नाम से उल्लेख मिलता है। प्रदेश के साल वनों में कहीं-कहीं यह पेड़ मिल जाता है। इस पेड़ की छाल हटाने पर एक गाढ़ा लाल रंग का स्राव मिलता है, जो मधुमेह के इलाज में काम आता है। इसी तरह से लक्ष्मीतरु को दक्षिण अमेरिकी मूल का माना जाता है। यह नर्मदापुरम संभाग के कई जिलों में मिलता है। इसके पत्तों से कैंसर के इलाज में काम आने वाली औषधियों का निर्माण होता है।

बालाघाट में वैनगंगा के जलस्तर में तेजी से आ रही गिरावट

-शहरवासियों में पेयजल की समस्या बढ़ती जा रही

बालाघाट। जागत गांव हमार

बालाघाट की जीवनदायिनी कही जाने वाली वैनगंगा का जलस्तर गिर रहा है। शहर वासियों भी इसी के पानी पर निर्भर है. ऐसे में जलस्तर गिरने से लोगों को पीने के पानी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इस बार दिसंबर-जनवरी के जलस्तर को देखें, तो बीते सालों के मुकाबले नदी ज्यादा सूख गई है। इससे न सिर्फ पानी की बल्कि पर्यावरणीय संकट की भी आहट सुनाई पड़ रही है। स्थानीय लोग बताते है कि यह नदी पहले के मुकाबले अब जल्दी सुख रही है। इसका कारण नदी से रेत का उत्खनन है। दरअसल, रेत में जल को रोकने क्षमता होती है। बालू केसिंग का काम करते है, जिससे पानी जमीन के भीतर पहुंचता है। भूमिगत जल स्तर भी बढ़ता है। इससे आसपास के जल स्त्रोत जैसे कुएं, तालाब और बोरवेल भी चार्ज रहते हैं। और पानी की समस्या में कमी आती है, लेकिन वैनगंगा अब समय से पहले सुख रही है।

नदी सूखने से लोग परेशान

सामान्य दिनों में लगभग एक व्यक्ति 135 लीटर पानी खर्च करता है। ऐसे में बालाघाट को हर दिन 20 लाख मिलियन लीटर पानी की सप्लाई करनी पड़ती है। वहीं, गर्मी के दिनों में कूलर के इस्तेमाल के कारण पानी की मांग भी बढ़ जाती है। ऐसे में नदी के सूखने से गर्मी के दिनों में लोगों को दैनिक उपयोग सहित पेयजल के लिए भी संघर्ष करना पड़ सकता है।

वन्य प्राणियों के लिए भी संकट

वैनगंगा के किनारे पर जंगल लगा हुआ है। ऐसे में वन्य प्राणी भी पानी के लिए नदी पर ही आश्रित है। ऐसे में नदी के सुखने से इनके लिए भी संकट खड़ा हो सकता है। जब पानी और खाने की कमी होती है, तो वन्य प्राणी भी रिहायशी इलाकों की तरफ बढ़ते है। मानव-और वन्य प्राणियों की बीच टकराव होता है।

जल संरक्षण के लिए हर साल स्टॉप डैम बनाए जाते हैं। ऐसे में इस साल भी स्टॉप डैम बनाए जाएंगे। इसके लिए टेंडर निकाल दिए गए हैं। टेंडर पास होते ही शुरू हो जाएगा।

बीडी कतरोलिया, सीएमओ नगरपालिका बालाघाट

गेंहू के बीज अमानक पाए जाने पर नोटिस

रीवा। उप संचालक कृषि यूपी बागरी ने गेंहू के बीज जांच में अमानक पाए जाने पर दो बीज विक्रेताओं को कारण बताओ नोटिस दिया है। जारी अलग-अलग नोटिस के अनुसार मेसर्स पयासी कृषक सहायता केन्द्र बीड़ा विकासखंड सिरमौर द्वारा बेचे गए गेंहू के एचआई 8759 सीआई बीज का नमूना लेकर जांच कराए जाने पर अमानक पाया गया। इसी तरह मेसर्स राम कृषि सेवा केन्द्र विकासखंड रीवा द्वारा बेचे गए गेंहू के एचआई 8713 सीआईआईबी बीज के नमूने भी जांच में अमानक पाए गए। उप संचालक ने दोनों बीज विक्रेताओं को अमानक बीजों के लाट और बैच नंबर जिन किसानों को बिक्री की गई है उनकी सूची तथा विक्रय के प्रमाण पत्र सात दिवस में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। समय सीमा का पालन न करने पर बीज नियंत्रण आदेश 1983 तथा बीज नियंत्रण अधिनियम 1966 के प्रावधानों के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. **प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति,** राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406
2. **प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर,** आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दड्डद्धद्धiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380
3. **डा. वीरेन्द्र कुमार,** प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304
4. **डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक,** मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncgupt-abau@gmail.com, मोबा- 8789708210
5. **डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184
6. **डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर,** एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901
7. **डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर** आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144
8. **डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर,** परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793
9. **डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक,** मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836
10. **डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ** (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670
11. **रोमा वर्मा,** सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। **संपादकः** अजय कुमार द्विवेदी, **स्थानीय संपादकः अरविंद मिश्रा, संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)